



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 2010/ज्येष्ठ 12, 1932

No. 146]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 2010/JYAISTHA 12, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

(बागवानी प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जून, 2010

फा. सं. 11-7/2009-बागवानी-IV.—कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीपीए) का मूल रूप से रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग में 1981 में गठन किया गया था, जिसने 1993 से कृषि एवं सहकारिता विभाग में कार्य करना शुरू कर दिया। 1996 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इस समिति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और बागवानी में प्लास्टिक के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समन्वित रीति से इसके कार्यों का केन्द्रण करने के लिए एनसीपीए का बागवानी में राष्ट्रीय अनुप्रयोग समिति (एनसीपीएएच) के रूप में 2001 में पुनर्गठन किया गया था। तत्पश्चात् एनसीपीएएच का दिनांक 15-6-2007 को 3 वर्ष की अवधि के लिए पिछली बार पुनर्गठन किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत बागवानी में राष्ट्रीय प्लास्टिकलचर अनुप्रयोग समिति (एनसीपीएएच) (एतश्मिन समिति के रूप में संदर्भित) का पुनर्गठन किया जाए। समिति का गठन एवं विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं :-

क. गठन

- |  |            |
|--|------------|
| 1. केन्द्रीय कृषि मंत्री                     | —अध्यक्ष   |
| 2. कृषि राज्य मंत्री                         | —उपाध्यक्ष |
| 3. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग             | —सदस्य     |
| 4. सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग        | -तदैव-     |
| 5. सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भा.कृअ.प.)     | -तदैव-     |
| 6. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय                  | -तदैव-     |
| 7. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय                | -तदैव-     |
| 8. अपर सचिव, बागवानी का आई./सी. कृषि एवं सह. | -तदैव-     |
| 9. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सह.                 | -तदैव-     |
| 10. उप महानिदेशक (बागवानी), भा.कृअ.प.        | -तदैव-     |
| 11. वित्तीय सलाहकार (कृषि एवं सह. विभाग)     | -तदैव-     |

12. प्रमुख सलाहकार (कृषि), योजना आयोग —सदस्य
13. संयुक्त सचिव(एनएचएम), (कृषि एवं सह.) —तदैव-
- चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि**
14. प्रमुख सचिव (कृषि/बागवानी), कर्नाटक सरकार —सदस्य
15. प्रमुख सचिव (कृषि/बागवानी), गुजरात सरकार —तदैव-
16. कृषि उत्पादन आयुक्त, पंजाब सरकार —तदैव-
17. प्रमुख सचिव (बागवानी), उत्तराखंड —तदैव-
- नाबार्ड के प्रतिनिधि**
18. मुख्य महा प्रबंधक, नाबार्ड, मुंबई —सदस्य
- भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि**
19. निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली —सदस्य
- दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति**
20. उप कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर —सदस्य
21. उप कुलपति, बाला साहेब सावंत विद्यापीठ, डपोली —तदैव-
- हाई-टैक बागवानी उद्योग के प्रतिनिधि**
22. अध्यक्ष, भारतीय सिंचाई संघ, बंगलौर —सदस्य
23. ग्रीन हाउस विनिर्माताओं के प्रतिनिधि —तदैव-
24. माइक्रो प्रोपेगेशन (टीसी) इकाइयों के प्रतिनिधि —तदैव-
- किसान संघ**
25. अध्यक्ष, भारतीय बागवानी संघ (सीआईएच), पुणे, महाराष्ट्र —सदस्य
- सदस्य-सचिव**
26. बागवानी आयुक्त —सदस्य सचिव
- (ख) विचारार्थ विषय**
- उत्पाद की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिये जल तथा सूर्य के प्रकाश जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के विशेष संदर्भ में कृषि में प्लास्टिक के उपयोग (प्लास्टिकल्चर) के जरिये बागवानी/कृषि विकास के संवर्धन में समन्वय स्थापित करना ।
  - देश में प्लास्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिये उचित नीतिगत उपाय संस्तुत करना ।
  - ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, संरक्षित खेती, सामुदायिक टैंक, फसलोपरान्त प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न प्लास्टिकल्चर अनुप्रयोगों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिये सुविधा प्रदान करना ।
  - प्लास्टिकल्चर में आंकड़ा आधार तैयार करने तथा अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन को कारगर बनाना ।
  - प्लास्टिकल्चर में प्रयुक्त उत्पादों के लिये गुणवत्ता मानकों के विकास में उचित कार्यनीतियों का सुझाव देना तथा क्षेत्र में ऐसे मानकों की उचित स्वीकृति सुनिश्चित करना ।
  - सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जो इन स्कीमों में प्लास्टिकल्चर घटक के संबंध में एनएचएम, टीएमएनई, आर के वी वाई आदि से जुड़ी हुई हैं, के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये तरीके सुझाना ।
  - देश में सामान्य रूप से प्रेसीजन फार्मिंग विधियों तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के समग्र विकास तथा विशेष रूप से प्रेसीजन फार्मिंग विकास केन्द्रों के निष्पादन की प्रभावी मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण करना ।
  - देश में प्लास्टिकल्चर के संवर्धन से जुड़ा कोई अन्य मामला ।
2. एनसीपीएच की अवधि संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी । अध्यक्ष, एनसीपीएच की सहमति से गैर-सरकारी सदस्य पद ग्रहण करेंगे । समिति की बैठक जब कभी आवश्यक होगी तभी आयोजित की जायेगी लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी । समिति सरकार को वार्षिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

3. समिति के लिए अपेक्षित लिपिकीय सहायता जारी रहेगी जिसे भारतीय पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से लिए गए कर्मिकों द्वारा सेवा के लिए एनसीपीएच के केन्द्रीय समन्वय कक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। सदस्य सचिव एनसीपीएच के दैनिक क्रियाकलापों को देखेंगे तथा निकाय के मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करेंगे।

4. समिति के कार्य व्यापार संबंधी यात्राओं के संबंध में राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधी व्यय को समिति के लिए आर्बिट्रर राशियों में से पूरा किया जायेगा। अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में संगत व्यय उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा।

डा. गोरख सिंह, बागवानी आयुक्त

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

(HORTICULTURE DIVISION)

### RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2010

**No. 11-7/2009-Hort. IV.**—The National Committee on use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally constituted in the Department of Chemicals and Petrochemicals in 1981 has been functioning in the Department of Agriculture and Cooperation since 1993. It was reconstituted in 1996. In order to make this Committee more effective and to focus its endeavour in a coordinated manner for promoting the applications of plastics in Horticulture, NCPA was reconstituted in 2001 as National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH). Thereafter, NCPAH was last constituted on 15-06-2007 for a period of three years. It has been decided to reconstitute National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH) (hereinafter referred to as the Committee) under the Department of Agriculture and Cooperation. The composition and Terms of Reference (TOR) of the Committee are as under :—

#### A. Composition

1. Union Agriculture Minister	—Chairman
2. Minister of State for Agriculture	—Vice-Chairman
3. Secretary (A&C), DAC	—Member
4. Secretary, Deptt. of Chemicals and Petrochemicals	-do-
5. Secretary (DARE) & DG (ICAR)	-do-
6. Secretary, Ministry of Water Resources	-do-
7. Secretary, M/o Panchayati Raj	-do-
8. Addl. Secretary I/c of Horticulture, DAC	-do-
9. Agriculture Commissioner, DAC	-do-
10. Dy. Director General (Hort.), ICAR	-do-
11. Financial Adviser, DAC	-do-
12. Principal Adviser (Agri.), Planning Commission	-do-
13. Joint Secretary (NHM), DAC	-do-

#### Representative of four State Governments

14. Principal Secretary (Agri/Hort.), Govt. of Karnataka	—Member
15. Principal Secretary (Agri/Hort.), Govt. of Gujarat	-do-
16. Agriculture Production Commissioner, Govt. of Punjab	-do-
17. Pr. Secretary (Horticulture), Government of Uttarakhand	-do-

#### Representative of NABARD

18. Chief General Manager, NABARD, Mumbai	—Member
---	---------

**Representative of Bureau of Indian Standards**

19. Director, BIS, New Delhi —Member

**Vice-Chancellors of two State Agricultural Universities**

20. Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore —Member  
 21. Vice-Chancellor, Balasaheb Sawant Krishi Vidyapeeth, Dapoli -do-

**Representative of Hi-tech Horticulture Industry**

22. President, Irrigation Association of India, Bangalore —Member  
 23. Representative of Green House Manufacturers -do-  
 24. Representative of Micropropagation (TC) Units -do-

**Farmer's Associations**

25. President, Confederation of Indian Horticulture (CIH), Pune, Maharashtra —Member

**Member Secretary**

26. Horticulture Commissioner —Member Secretary

**B. Terms of Reference**

- (i) To coordinate in promotion of horticulture/agriculture development through use of plastics in agriculture (Plasticulture) with special reference to harnessing the available natural resources such as water and sunlight in improving the productivity and quality of the produce.
- (ii) To recommend suitable policy measures for promotion of plasticulture in the country.
- (iii) To facilitate increased adoption of various Plasticulture applications like drip and sprinkler irrigation systems, protected cultivation, community tanks, post harvest management, etc.
- (iv) To facilitate in promotion of Research and Development and to build data-base in plasticulture.
- (v) To suggest suitable strategies in development of quality standards for products used in plasticulture and to ensure proper adoption of such standards in the field.
- (vi) To suggest ways and means for effective implementation of Centrally Sponsored Schemes on Micro-irrigation having integration with NHM, TMNE, RKVY, etc. in relation to plasticulture component in these schemes.
- (vii) To supervise and monitor effectively the performance of Precision Farming Development Centres (PFDCs) in particular and overall development of Precision Farming methods and hi-tech interventions in general in the country.
- (viii) Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.

2. The term of NCPAH will be for a period of three years from the date of issue of the Resolution. The non-official members shall hold office with the pleasure of the Chairman, NCPAH. The committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The Committee shall submit its report to the Government on annual basis.

3. The Secretarial assistance required for the committee will continue to be provided by the Central Coordination Cell of NCPAH serviced by personnel drawn from Indian Petrochemicals Ltd. or any other suitable agency. The Member Secretary will oversee day to day activities of NCPAH and function as Chief Executive on the body.

4. The expenditure on TA/DA of the Vice-Chancellors of State Agricultural Universities and the non-official members in connection with the journeys undertaken on Committee's business will be met out of the funds allocated for the Committee. Corresponding expenditure in respect of other ex-officio members will be borne by their respective departments.

Dr. GORAKH SINGH, Horticulture Commissioner